EDITORIAL

BSNL - STRUGGLING EMPLOYEES AND THEIR UNCERTAIN FUTURE

Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) was once one of the strongest and most reliable telecom companies in India. Under government ownership, it played a key role in extending communication services to remote areas of the country. However, today, its employees are facing uncertainty and crisis. Aggressive competition from private companies, government apathy, and internal administrative weaknesses have left BSNL employees worried about their future.

Several factors have contributed to BSNL's current situation. The key reasons include:

1. Technological Lag - BSNL's delayed entry into 4G and 5G networks has been one of its biggest weaknesses. While private companies have already launched 5G services, BSNL is still struggling with 4G expansion.

2. Inefficient Management Policies - As a government-owned company, decision-making processes are slow. Private companies make quick decisions to establish themselves in the market, whereas BSNL gets stuck in bureaucratic red tape.

3. Intense Competition from Private Players - Companies like Jio, Airtel, and Vodafone-Idea have attracted BSNL's customers with aggressive pricing and better network quality.

4. Government Apathy The government has provided financial packages to revive BSNL multiple times, but no long-term strategic plan has been implemented to make it profitable.

5. Employee Uncertainty - Delayed salary payments, fear of layoffs, and growing concerns about the future have demoralized employees. The Voluntary Retirement Scheme (VRS) led to the exit of thousands of employees, reducing the workforce significantly.

BSNL employees are currently facing mental stress and financial instability. Delayed salaries, lack of promotions, and workplace uncertainty have shattered their morale. Some employees are forced to seek jobs in private companies, while others are waiting for retirement.

Employee Struggles and Wage Issues

Without stabilizing the condition of BSNL employees, it is difficult to imagine the company's revival. Over 60% of non-executive employees have yet to receive their annual salary increments, and **their wage revision has been pending since January 1, 2017. They are still working on the 2007 pay scale, which has pushed them towards financial distress. This affects their children's education, healthcare, and overall quality of life.**

Despite repeated appeals to the government and BSNL management for wage revision, no resolution has been reached. Even after multiple protests and movements, a committee was formed with officials and labour union representatives to determine the pay scale. However, due to the rigid stance of management officials, wage revision has not been finalized despite several meetings. The government and management must address this issue promptly to boost employee morale, enabling them to contribute effectively to the company's growth.

Promotion Challenges

BSNL has two promotion systems in place:

(a) Promotion through competitive exams

(b) Time-bound financial upgradation

Currently, both systems are nearly defunct. Competitive exams for promotions have not been conducted in over half of the regions due to arbitrary restructuring, which has adversely affected employees' career progression. The time-bound financial upgradation system introduced in 2008 has become irrelevant, yet the management refuses to implement a new system despite continuous demands from labour unions. As a result, promotion opportunities have nearly disappeared, leading to a decline in employee morale and work efficiency.

Another major issue is the employee transfer policy. Welfare provisions under Rule-8 and Rule-9, which allowed employees to transfer to their spouse's workplace or to care for elderly and ailing parents, have beer abolished. This has created immense difficulties for employees working in remote areas who are unable to relocate to their preferred location

Future of BSNL's Young, Highly Educated Workforce

BSNL has recruited many highly educated young employees, but their future remains uncertain. They neither receive appropriate salaries nor have a structured promotion system. Even retirement benefits prescribed by India's Public Sector Enterprises Department have not been implemented. **Without a proper human resource development framework, the company's revival remains questionable.**

Government Revival Package - Too Little, Too Late?

The government has announced a 1.64 lakh crore revival package for BSNL and plans to launch 4G/5G services, but rapid execution is necessary. If BSNL is to become competitive again, the following steps must be taken:

1. Technological Upgradation-4G and 5G services must be implemented quickly to strengthen its market position.

2. Management Improvement - The decision-making process should be expedited, and modern management strategies should be adopted.

3. Concrete Policy for Employees - Salaries should be paid on time, the risk of layoffs should be minimized, and appropriate steps should be taken to boost employee morale.

4. Aggressive Market Strategy Attractive plans and better customer service should be used to regain consumer trust.

The crisis that BSNL employees are facing today is not just about a single organization but also reflects government policies and the state of public sector enterprises. If the government and management do not take the right steps in time, this institution may become completely irrelevant. **Protecting employees' interests and making BSNL competitive again is the need of the hour. If the right decisions are made, this company can not only revive but also regain the trust of millions of employees and customers.**

संपादकीय

बीएसएनएल – बिलखते कर्मचारी और उनका भविष्य

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कभी देश की सबसे मजबूत और भरोसेमंद दूरसंचार कंपनियों में से एक हुआ करता था। सरकारी संरक्षण में पनपा यह उपक्रम देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक भी संचार सेवाएँ पहुँचाने में अग्रणी था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि इसके कर्मचारी असमंजस और संकट के दौर से गुजर रहे हैं। निजी कंपनियों की आक्रामक प्रतिस्पर्धा, सरकारी उदासीनता और संगठन के भीतर की प्रशासनिक कमजोरियों के चलते बीएसएनएल के कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

बीएसएनएल की मौजूदा हालत के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

1. तकनीकी पिछड़ापन बीएसएनएल का 4जी और 5जी नेटवर्क में देर से प्रवेश करना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। निजी कंपनियाँ जहाँ 5जी सेवाएँ शुरू कर चुकी हैं, वहीं बीएसएनएल अभी भी 4जी विस्तार में संघर्ष कर रहा है।

2. प्रबंधन में लचर नीति सरकारी कंपनी होने के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी रही है। निजी कंपनियाँ जहाँ त्वरित निर्णय लेकर बाजार में खुद को स्थापित कर लेती हैं, वहीं बीएसएनएल सरकारी फाइलों में उलझा रहता है।

3. निजी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा.जियो, एयरटेल और वोडाफोन–आइडिया जैसी कंपनियों ने आक्रामक कीमतों और बेहतर नेटवर्क के जरिए बीएसएनएल के ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया।

4. सरकारी उदासीनता सरकार ने कई बार बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए पैकेज दिए, लेकिन कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जिससे यह दीर्घकालिक रूप से लाभदायक हो सके।

5. कर्मचारियों की अनिश्चित स्थिति वेतन भुगतान में देरी, छंटनी की आशंका और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता ने कर्मचारियों का मनोबल गिरा दिया है। वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) के माध्यम से हजारों कर्मचारियों को हटाया गया, जिससे कार्यबल भी सीमित हो गया।

बीएसएनएल के कर्मचारी इस समय मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। समय पर वेतन न मिलना, प्रमोशन न होना और कार्यस्थल पर अनिश्चितता की स्थिति ने उनके मनोबल को तोड़ दिया है। कुछ कर्मचारियों को मजबूरन निजी कंपनियों में नौकरी तलाशनी पड़ रही है, जबकि कई सेवानिवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं।

बीएसएनएल कर्मचारियों की स्थिति सुदृढ़ बनाए बिना कंपनी के पुनरुत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती। बीएसएनएल कर्मचारियों के नन एग्जीक्यूटिव संवर्ग में लगभग 60 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी से अभी तक वंचित हैं। जबकि इनका वेतन संशोधन 01.012017 से लंबित है। कर्मचारी 2007 के वेतनमान पर कार्य करने को मजबूर हैं। शनैः शनैः कर्मचारी आर्थिक विपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। जिसका प्रभाव उनके बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य व्यवस्था एवं उचित रहन–सहन दुर्लभ होते जा रहा है। बीएसएनएल कर्मचारियों ने लगातार वेतन संशोधन के लिए सरकार एवं बीएसएनएल प्रबंधन का ध्यान विभिन्न माध्यमों से आकृष्ट कराते आ रहे हैं। कई आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने के बाद सरकार की ओर से नॉन–एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण हेतु अधिकारियों एवं मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई है। परंतु प्रबंधन पक्ष के अधिकारियों के हठधर्मिता के कारण अनेकों बैठकों के बावजूद वेतनमान का निर्धारण नहीं हो पाया है। प्रबंधन एवं सरकार को कर्मचारियों की इस पीड़ा से उभारने के लिए शीघ्र वेतन संशोधन करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि कर्मचारी कंपनी के उत्थान में बेहतर योगदान दे सकें।

पदोन्नति की समस्याएं

बीएसएनल में कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु दो प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।

(क) प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति की व्यवस्था एवं समयबद्ध आर्थिक उन्नयन की व्यवस्था।

वर्तमान में यह दोनों व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति हेतु प्रतिस्पर्धा की परीक्षाएं आधे से अधिक परिमंडल में आयोजित नहीं की जा रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ की संवर्गों के पुनर्गठन के नाम पर आधे से अधिक परिमंडलों को कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए आवश्यकता से अधिक घोषित कर दिया गया। यह कार्य बिना वस्तु स्थिति को ठीक से समझे कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों के पदोन्नति पर प्रतिकूल असर हो रहा है। जहां तक समयबद्ध आर्थिक उन्नयन का सवाल है यह व्यवस्था 2008 में लागू की गई थी और वर्तमान स्थिति में यह पूर्णतया अप्रासंगिक हो चुकी है। परंतु मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा बार–बार मांग करने के बावजूद नई व्यवस्था लागू नहीं की जा रही है। जिससे कुल मिलाकर कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता प्रायः बंद हो चुका है। यह स्थिति कर्मचारियों के मनोबल एवं कार्य दक्षता के गुणात्मक गिरावट का कारण बन रही है। एक और ज्वलंत समस्या कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति है। जिसके तहत नियम 8 एवं नियम के तहत स्थानांतरण के लिए दिए गए कल्याणकारी प्रावधानों को अमानवीयता के साथ समाप्त कर दिया गया है। अब दूरदराज क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके पत्नी के कार्य स्थल पर स्थानांतरण नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार वृद्ध एवं बीमार माता–पिता के सेवा हेतु उन्हें उनके पैतृक इलाके में स्थानांतरण नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर बीएसएनएल के कर्मचारियों की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इस स्थिति में बीएसएनएल के उत्थान की बात एक थोथी दलील ही लगता है।

बीएसएनल में भर्ती किए गए उच्च शिक्षित युवा कर्मचारी भी हैं। उनके भविष्य की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। ना तो उन्हें उचित वेतनमान मिल रहा है और ना ही पदोन्नति की सम्यक व्यवस्था है। ऐसे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को भी लागू नहीं किया गया है। बीएसएनल में मानव संसाधन विकास की शून्य व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है जो न्याय संगत नहीं है।

हालांकि, सरकार ने बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज दिया है और 4जी/5जी सेवाएँ शुरू करने की योजना बनाई है, लेकिन इस पर तेजी से काम करना आवश्यक है। यदि बीएसएनएल को फिर से प्रतिस्पर्धी बनाना है, तो निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

1. तकनीकी उन्नयन 4जी और 5जी सेवाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिल सके।

2. प्रबंधन सुधार निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज किया जाए और आधुनिक प्रबंधन रणनीतियों को अपनाया जाए।

3. कर्मचारियों के लिए ठोस नीति वेतन समय पर दिया जाए, छंटनी की आशंका को कम किया जाए और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उचिंत कदम उठाए जाएँ।

4. बाजार में आक्रामक रणनीति आकर्षक प्लान और बेहतर ग्राहक सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं का भरोसा फिर से जीता जाए।

बीएसएनएल के कर्मचारी आज जिस संकट से गुजर रहे हैं, वह केवल एक संगठन का नहीं, बल्कि सरकार की नीति और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति का भी प्रतिबिंब है। यदि सरकार और प्रबंधन ने समय रहते सही कदम नहीं उठाए, तो यह संस्था पूरी तरह से अप्रासंगिक हो सकती है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और बीएसएनएल को फिर से प्रतिस्पर्धी बनाना समय की माँग है। यदि सही निर्णय लिए गए, तो यह कंपनी न केवल उभर सकती है बल्कि लाखों कर्मचारियों और ग्राहकों का विश्वास भी फिर से जीत सकती है।